डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और फिनटेक के माध्यम से समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना

- श्री संजय मल्होत्रा

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) के इस 6वें संस्करण में भाग लेकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह एक प्रमुख मंच है जहां प्रौद्योगिकी के जादूगर वित्त के विशेषज्ञों के साथ परिचर्चा करते हैं। यह एक अनूठा मंच है जहां युवा नवप्रवर्तक, साहसिक विचारों से भरे हुए, अनुभवी विशेषज्ञों के स्थिर ज्ञान के साथ जुड़ते हैं। यह तालमेल जो आम चुनौतियों के समाधान को आकार देता है, जीएफएफ की सच्ची भावना को दर्शाता है। यह आयोजन डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बने रहने की भारत की महत्वाकांक्षा को भी दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में, जीएफएफ ने अपनी ताकत और बढ़ाई है। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए आयोजकों को बधाई देता हूं।

आज मैं अपनी टिप्पणी में हमारी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और फिनटेक यात्रा पर विचार करना चाहता हूं, जो समावेशन और स्थिरता को गहरा और व्यापक बनाने का अगला चरण है, और फिनटेक के लिए इन अवसरों को ठोस परिणामों में बदलने के लिए आगे का रास्ता है।

भारत की विकास गाथा के इंजन के रूप में डीपीआई

डीपीआई पिछले एक दशक में भारत के डिजिटल परिवर्तन को रेखांकित करता है। यह तीन परतों पर टिका हुआ है, जिन्होंने समावेशन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और बड़े पैमाने पर नवाचार को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पहला, 1.4 बिलियन से अधिक नामांकन के साथ आधार द्वारा संचालित पहचान परत ने पहचान को तुरंत प्रमाणित करना संभव बना दिया है। इसने लाखों लोगों को इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी के माध्यम से बैंक खाते खोलने और औपचारिक वित्तीय प्रणाली में भाग लेने में सक्षम बनाया है। यह सरकारी लाभों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के मूल में है।

दूसरा, भुगतान परत जो पहचान को कार्रवाई में बदल देती है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) ने माइक्रो-एटीएम के माध्यम से बैंकिंग को सक्षम बनाया है और दूरदराज के स्थानों में भी पहुंच की सुविधा प्रदान की है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने लगभग 490 मिलियन अद्वितीय उपयोगकर्ताओं को हर महीने लगभग 20 बिलियन लेनदेन करने की अनुमति दी है, जो वैश्विक वास्तविक समय भुगतान मात्रा का लगभग आधा है।

तीसरा, डेटा लेयर ने वित्तीय सेवाओं को वितरित करने के तरीके को फिर से आकार दिया है। उदाहरण के लिए, किसी भी सरकारी विभाग को लें। प्रत्येक विभाग में जबरदस्त मात्रा में डिजिटलीकरण हुआ है। मैं पहले राजस्व विभाग में था। लगभग सभी आय डेटा अब डिजिटल हो गए हैं, भारत में आयकर रिटर्न दाखिल करने में केवल कुछ मिनट लगते हैं। औसतन, रिटर्न 10 दिनों में संसाधित किए जाते हैं और कई करदाताओं को 24 घंटे के भीतर अपना रिफंड प्राप्त होता है। हम टैक्स फाइलिंग और प्रोसेसिंग सिस्टम में दुनिया में अग्रणी हैं।

इसी तरह, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)। यह एक अनूठा मॉडल है जिसकी दुनिया में कोई समानता नहीं है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र - सभी अलग-अलग विधानसभाओं द्वारा पारित एक अलग जीएसटी क़ानून के साथ, लेकिन राज्य के नाम को छोड़कर अन्य सभी समान है। जीएसटी का यह एकीकरण वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) द्वारा प्रदान किए गए आधार के कारण संभव हुआ है। इस सब ने डेटा परत को शामिल करते हुए बहुत सारे डिजिटल डेटा बनाए हैं। इसके अलावा, 590 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ डिजिलॉकर ने नागरिकों को डिजिटल रूप में दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत और साझा करने में सक्षम बनाया है।

डीपीआई के संपूरक के रूप में फिनटेक

डीपीआई की इन तीन परतों की सराहना करते हुए, हमारे पास एक जीवंत फिनटेक इकोसिस्टम है। डीपीआई की नींव फिनटेक को न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की चुनौतियों का

* 8 अक्टूबर 2025, मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा का मुख्य भाषण।

समाधान करने के लिए तेजी से स्थापित करने, तेजी से स्केल करने और लक्षित समाधान प्रदान करने की अनुमति देती है। भारत आज 10,000 से अधिक फिनटेक कंपनियों का घर है, जिनका संचयी निवेश पिछले एक दशक में 40 बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक है।

इस क्षेत्र की अभूतपूर्व वृद्धि और भविष्य की क्षमता मजबूत डीपीआई के अलावा कई प्रमुख ताकतों पर आधारित है। इनमें कुशल प्रौद्योगिकी प्रतिभा का एक बड़ा और गहरा पूल, भुगतान, ऋण, बीमा, पेंशन, धन प्रबंधन आदि तक फैला एक जीवंत वित्तीय पारितंत्र शामिल है, जो फिनटेक नवाचार का समर्थन कर रहा है, और नीतियों और नियामक ढांचे को सक्षम कर रहा है जो फिनटेक की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

फिनटेक इकोसिस्टम के साथ नियमित जुड़ाव इस दृष्टिकोण के केंद्र में है। आरबीआई फिनटेक क्षेत्र के साथ जुड़ने में सक्रिय रहा है, जैसा कि अकेले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान फिनटेक संस्थाओं के साथ लगभग 500 बार हुई बातचीत से पता चलता है। इसके अलावा, फिनटेरैक्ट और फिनक्वेरी जैसे संरचित प्लेटफार्मों के माध्यम से, हम फिनटेक इकोसिस्टम में इनोवेटर्स और उद्यमियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करते हैं। मार्च 2024 से, हमने फिनटेरैक्ट के तहत 15 संरचित सत्र आयोजित किए हैं, जिसमें 1,100 से अधिक फिनटेक प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अलावा, जून 2024 से फिनक्वेरी के तहत 600 से अधिक प्रतिभागियों के साथ 14 खुली बातचीत आयोजित की गई है।

रिज़र्व बैंक ने गतिविधियों, उत्पादों और प्रौद्योगिकियों पर महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने के लिए एक फिनटेक रिपॉजिटरी भी स्थापित की है, जिससे फिनटेक क्षेत्र के लिए अधिक सूचित और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण संभव हो सके।

हमने फिनटेक क्षेत्र में विविधता को पहचानते हुए, अब तक फिनटेक क्षेत्र में एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) को मान्यता दी है। यह उन फिनटेक को सक्षम करेगा जो उद्योग द्वारा विकसित आधारभूत अभिशासन मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ एक सुविचारित ढांचे के भीतर काम करने के लिए सीधे विनियमित नहीं हैं।

पिछले एक दशक में, भारत ने दिखाया है कि कैसे प्रौद्योगिकी, सोच-समझकर डिजाइन और बड़े पैमाने पर कार्यान्वित की गई, सतत आर्थिक विकास के लिए एक सशक्त गुणक हो सकती है। फिनटेक उद्योग ने सस्ती कीमत पर जनसंख्या के पैमाने पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना संभव बना दिया है। हम अर्थव्यवस्था के सामूहिक लाभ के लिए डीपीआई और वित्तीय इकोसिस्टम का उपयोग करने के लिए फिनटेक के लिए सुविधा जारी रखेंगे। सार्वजनिक रेल और निजी नवाचार के बीच यह तालमेल, भुगतान के डिजिटलीकरण सहित कई क्षेत्रों में भारत की सफलता का आधार रहा है।

भारत की डिजिटल यात्रा का अगला चरण

भारत की डिजिटल यात्रा का पहला चरण नींव बनाने और बचत, बीमा, निवेश जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने के बारे में था। अगला चरण जिम्मेदारी से डेटा का उपयोग करके प्रभाव को सार्वभौमिक और गहन करने के बारे में है। मैं पांच क्षेत्रों के बारे में बात करूंगा। इन सभी क्षेत्रों में कुछ काम किया गया है लेकिन अभी और भी काम करने की जरूरत है। ये हैं: (ए) वित्तीय डेटा का एकत्रीकरण और लाभ उठाना; (ख) डिजिटल रुपया; (ग) एसेट टोकनाइजेशन; (घ) कृत्रिम बुद्धिमत्ता; और (ई) डिजिटल धोखाधड़ी।

वित्तीय डेटा का एकत्रीकरण और लाभ उठाना

अकाउंट एग्रीगेटर (एए)

सबसे पहले, हमें वित्तीय समावेशन को व्यापक और गहरा करने के लिए विभिन्न डेटा स्रोतों में डेटा एकीकरण के लिए डीपीआई विकसित करने की आवश्यकता है। अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क ऐसा ही एक प्रयास है। यह व्यक्तियों को अपने वित्तीय डेटा को विनियमित संस्थाओं के साथ सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए सशक्त बना रहा है। इस पारितंत्र में 17 एए, 650 वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू), 150 वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी), 160 मिलियन खातों की सेवा और एए द्वारा संसाधित एफआईयू से 3.66 बिलियन डेटा अनुरोधों के साथ उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। जीएसटीएन जैसे कई महत्वपूर्ण सरकारी स्वामित्व वाले डेटा स्रोतों को एए ढांचे में शामिल किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, अपनी ओर से ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं में सुधार करने, उपयोगकर्ता इंटरफेस को बढ़ाने, डेटा सुरक्षा को मजबूत करने और एए ढांचे के तहत सहमति प्रबंधन और डेटा साझाकरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए मानकों को पेश करने की प्रक्रिया में है।

हालांकि एए ढांचे के बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसकी सफलता दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर निर्भर करेगी, अर्थात् अधिक वित्तीय जानकारी के साथ एकीकरण, विशेष रूप से जानकारी जो किसी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है और खाता एग्रीगेटर्स के बीच अंतः परिचालनीयता।

यूएलआई

यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) डेटा एकत्रीकरण में एक और महत्वपूर्ण कदम है। ऋण समावेशी विकास की जीवनरेखा बनी हुई है। सरकार, आरबीआई और बैंकिंग प्रणाली के सर्वोत्तम प्रयासों और इस संबंध में की गई भारी प्रगति के बावजूद, एक विशाल ऋण अंतर अभी भी बना हुआ है। यूएलआई कुशल, डेटा-संचालित और समावेशी ऋण वितरण को सक्षम करके अंतर को पाटने का प्रयास करता है।

अगस्त 2023 में लॉन्च होने के बाद से 03 अक्टूबर 2025 तक, यूएलआई पायलट का विस्तार अब 120 डेटा स्रोतों/सेवाओं, बैंकों, एनबीएफसी, सहकारी बैंकों सहित 58 ऋणदाताओं तक हो गया है, जिसमें 3.2 मिलियन ऋण स्वीकृत हैं और 1.75 ट्रिलियन रुपये ऋण दिए गए हैं। यूएलआई वैकल्पिक क्रेडिट मॉडल बनाने के लिए ऋणदाताओं द्वारा डेटा के उपयोग को भी सक्षम कर रहा है, जिससे क्रेडिट इतिहास की कमी वाले नए क्रेडिट सेगमेंट में ऋण का विस्तार करने में मदद मिल रही है।

डिजिटल रुपया (e₹)

दूसरा, भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी), डिजिटल रुपया (e₹) DPI आर्किटेक्चर में एक महत्वपूर्ण नई रेल का प्रतिनिधित्व करता है. दिसंबर 2022 में लॉन्च होने के बाद से रिटेल e₹ पायलट में आज 19 बैंक और 7 मिलियन उपयोगकर्ता हैं जो व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) के साथ-साथ व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) लेनदेन को सक्षम करते हैं। यूपीआई के साथ अंतः परिचालनीयता भी उपयोगकर्ता सुविधा से समझौता किए बिना e₹ को व्यापक रूप से अपनाने में सक्षम हो रही है।

e₹ में प्रोग्रामेबिलिटी विशेषताएं उद्देश्य-संचालित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, सब्सिडी और लक्षित ऋण में नए प्रतिमान खोल रही हैं। इन सुविधाओं का लाभ कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाया गया है, जो सब्सिडी वितरण और डीबीटी को अधिक प्रभावी बनाने की क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात की जी-सफल योजना आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए प्रोग्राम करने योग्य सीबीडीसी (पी-सीबीडीसी) का उपयोग करती है, जिससे लाभार्थियों को जियोफेंसिंग क्षेत्र के भीतर केवल श्वेतसूची वाले कृषि-इनपुट पर सब्सिडी खर्च करने की अनुमति मिलती है। इसी तरह, आंध्र प्रदेश की दीपम 2.0 योजना पी-सीबीडीसी के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी प्रदान करती है, जिसे पंजीकृत गैस एजेंसियों द्वारा गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर भुनाया जाता है।

एसेट टोकनाइजेशन

तीसरा, एसेट टोकनाइजेशन भारतीय वित्तीय बाजारों के लिए पहुंच का विस्तार करने, पारदर्शिता में सुधार करने और स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से निपटान दक्षता बढ़ाने में नई संभावनाएं प्रदान करता है।

मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि रिज़र्व बैंक ने अगली पीढ़ी के वित्तीय बाजार बुनियादी ढांचे के रूप में एकीकृत बाजार इंटरफेस (यूएमआई) की अवधारणा तैयार की है। यूएमआई के पास थोक सीबीडीसी का उपयोग करके वित्तीय परिसंपत्तियों और निपटानों को टोकनाइज करने की क्षमता होगी। बाजार दक्षता में सुधार के लिए जमा प्रमाणपत्र जारी करने पर प्रारम्भिक पहल के शुरुआती परिणाम उत्साहजनक हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

चौथा, एआई दो पूरक तरीकों से डीपीआई की अगली पीढ़ी को मौलिक रूप से बढ़ाने की क्षमता रखता है। सबसे पहले, एआई को मौजूदा डीपीआई परतों में एकीकृत करके, उपयोगकर्ता अनुभव और दक्षता में काफी सुधार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए संवादात्मक भुगतान कम डिजिटल साक्षरता वाले उपयोगकर्ताओं के लिए लेनदेन को सरल बना सकता है और लाखों लोगों को

औपचारिक अर्थव्यवस्था में ला सकता है। दूसरा, एआई को सार्वजनिक वस्तुओं के बुनियादी ढांचे के रूप में विकसित किया जा सकता है।

आरबीआई द्वारा गठित फ्री-एआई समिति की रिपोर्ट ने वित्त में एआई के लिए मूलभूत सार्वजनिक वस्तुओं के निर्माण के महत्व पर भी प्रकाश डाला है, जिसमें एक मानकीकृत वित्तीय क्षेत्र डेटा बुनियादी ढांचा, गणना संसाधन और वित्तीय प्रणाली की जरूरतों के अनुरूप स्वदेशी एआई मॉडल का विकास शामिल है।

डिजिटल धोखाधड़ी

पांचवां, डिजिटल फाइनेंस के तेजी से विस्तार ने डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर खतरों जैसी नई चुनौतियां भी पैदा की हैं। रिज़र्व बैंक ने कई ग्राहक सुरक्षा उपाय स्थापित किए हैं, जैसे कि दो-कारक प्रमाणीकरण (2FA), फ़ाइल पर कार्ड का टोकनाइजेशन, और ग्राहकों को डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित करने के लिए लेनदेन को बंद करने का नियंत्रण प्रदान करना।

डिजिटल लेनदेन के प्रमाणीकरण पर हाल ही में घोषित सिद्धांत-आधारित ढांचा डिजिटल लेनदेन में विश्वास को मजबूत करते हुए उपभोक्ता सुविधा बढ़ाने के लिए और प्रोत्साहन प्रदान करेगा। विशेष इंटरनेट डोमेन, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए '.bank.in' और '.fin.in और लेन-देन और सेवा कॉल के लिए नामित नंबरिंग श्रृंखला, यानी '1600xx' और विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रचार संचार के लिए '140xx', डिजिटल लेनदेन में सुरक्षा और जनता के विश्वास को बढ़ाने के लिए अन्य पहल हैं।

रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा विकसित MuleHunter.ai को इस साल की शुरुआत में लगभग 5 बैंकों से बढ़ाकर 21 बैंक कर दिया गया है। पहले के दृष्टिकोणों के विपरीत, यह उन्हें म्यूल खातों का पता लगाने में सुधार के लिए सिस्टम-वाइड लर्निंग का उपयोग करने में सक्षम बना रहा है। डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीपीआईपी) पर भी काम चल रहा है, जो लगभग वास्तविक समय में धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम के लिए साझा खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए नवीनतम तकनीकों का लाभ उठाएगा।

इन उपायों से ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ेगी और डिजिटल भुगतान में विश्वास बढ़ेगा। हम सभी को अपने सिस्टम को संरक्षित, सुरक्षित और धोखाधड़ी से बचाने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

हम अपनी डिजिटल वित्त यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। पिछले दशक ने प्रदर्शित किया है कि कैसे प्रौद्योगिकी पहुंच का विस्तार कर सकती है और व्यवसायों को सशक्त बना सकती है। अगले चरण को इस मजबूत नींव पर निर्माण करना चाहिए, जबकि विश्वास और स्थिरता को अपने केंद्रीय विषय पर रखना चाहिए। इस अगले चरण में फिनटेक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी। फिनटेक ऐसे आर्किटेक्ट हो सकते हैं जो डिजिटल राजमार्गों का डिजाइन और निर्माण करते हैं और इस डिजिटल राजमार्ग पर ऐसे उत्पादों और सेवाओं का भी निर्माण करते हैं जो सामाजिक और आर्थिक मूल्य उत्पन्न करते हैं।

मैं फिनटेक उद्योग के लिए विचार करने के लिए पांच विचार रखना चाहता हूं।

1. **पहला, समावेशन के लिए निर्माण:** हालांकि अमीरों और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों तक पहुंच को गहरा करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है, तथापि समाज के अगम्य, अप्राप्य और असेवित वर्गों तक वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए निर्माण प्रणालियों को प्राथमिकता दें।
2. **दूसरा, ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण अपनाएं:** जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा, "अपने ग्राहकों के पहले से कहीं अधिक करीब पहुंचें। इतने करीब कि आप उन्हें बता दें कि उन्हें क्या चाहिए, इससे पहले कि वे खुद इसे महसूस करें। ऐसे उत्पादों और सेवाओं को डिजाइन करें जो उपयोग में आसान हों और सभी के लिए सुलभ हों, सहायक तकनीकों के साथ कमजोर समूहों जैसे वरिष्ठ नागरिकों, सीमित डिजिटल साक्षरता वाले व्यक्तियों और विशेष रूप से सक्षम लोगों को सुनिश्चित किया जाए। जैसा कि मैंने अन्य मंचों पर कहा है, सेवाओं को इतनी अच्छी तरह से डिजाइन करने का प्रयास करें कि पहली बार में ग्राहक सेवा की कोई आवश्यकता न हो।

3. **तीसरा, क्रेडिट डिलीवरी में नवाचार करें:** डिजिटल भुगतान की सफलता को क्रेडिट डिलीवरी तक बढ़ाएं, खासकर छोटे व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए।
4. **चौथा, विश्वास और अनुपालन को प्राथमिकता दें:** प्रत्येक उत्पाद और सेवा में उपभोक्ताओं के लिए मजबूत डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता और सुरक्षा उपायों को शामिल करें।
5. **पांचवां, थिंक ग्लोबल, एंकर लोकल:** अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ जुड़ना, सीख साझा करना, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना और डिजिटल फाइनेंस के भविष्य को आकार देने में भारत की भूमिका को मजबूत करना।

इन सिद्धांतों को अपनाकर और डीपीआई की भारत की अनूठी ताकत, एक जीवंत इकोसिस्टम, डिजिटल रूप से जुड़ी आबादी, सक्षम नीतियों और तकनीकी प्रतिभा का निर्माण करके, फिनटेक डिजिटल विभाजन को पाट सकता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकता है और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है।

ऐसा करने में, फिनटेक न केवल अपने स्वयं के विकास को सुरक्षित करेगा, बल्कि प्रगति को आगे बढ़ाने और विकसित भारत 2047 के विजन में योगदान देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस हॉल में, हमारे पास दूरदर्शिता और कार्य करने की क्षमता दोनों वाले लोग हैं। आइए हम इस अवसर का उपयोग करें और मिलकर समावेशी, टिकाऊ और नवाचार-संचालित विकास से साझा भविष्य को आकार दें।

धन्यवाद। जय हिंद।